करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

सितंबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **5**

- छत्तीसगढ़ क्वांटीफिएबल डाटा आयोग 5
- ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवॉर्ड समारोह 5
- 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' 6
- गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र 6
- 'इन्वेस्टगढ़-छत्तीसगढ़' के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण 7
- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस (IACP) अवॉर्ड 2021 7
- 'अतिरिक्त आहार' कार्यक्रम 8
- शिक्षक स्मृति पुरस्कार और राज्य शिक्षक सम्मान 8
- राज्य के तीन जीआई टैग्ड उत्पादों पर डाक विभाग द्वारा जारी विशेष आवरण का विमोचन 9
- तीजा-पोरा तिहार 9
- पोषण रथ 10
- हर ज़िले में हिन्दी मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 10
- 'हथकरघा एवं हस्तशिल्प' प्रदर्शनी 10
- 'मोर ज़िम्मेदारी' अभियान 11
- 'एकीकृत किसान पोर्टल' लॉन्च 11

नोट :

- 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण 12
- नगरीय निकाय: महिलाओं को 50% आरक्षण 12
- बाजरा मिशन शुरू, IIMR के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर 13
- बलरामपुर ज़िले के स्काउट-गाइड के छात्र राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित 13
- बस्तर: 'द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन' 14
- कोटेश्वर धाम में औषधीय प्रसंस्करण केंद्र 14
- छत्तीसगढ़ में खुलेगी बैडमिंटन अकादमी 15
- अब छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम 15
- स्थानीय निवासियों की परिभाषा में संशोधन 15
- प्रदेश का पहला स्टील ब्रिज 16
- छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 16
- हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ-साथ आईटीआई व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ 17
- छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय दर से आधी 17
- 'न्याय जनता के द्वार अभियान' 18
- NQAS के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में मिला द्वितीय पुरस्कार 19
- राजीव युवा मितान क्लब योजना 19
- तृतीय लिंग समुदाय के लिये नीति 20
- छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण में अव्वल 21
- प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में होगी 10 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना 22
- प्रदेश में रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को मिली सैद्धांतिक सहमति 22

नोट :

- आयुष्मान के लिये छत्तीसगढ़ को मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार 23
- 19वीं स्टेग छत्तीसगढ़ राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2021 23
- वाणिज्य उत्सव 24
- कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था 24
- मुकुंद रेडियो द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ का विमोचन 25
- नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर 25
- देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार 26
- कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की हल्दी व धनिया की नई प्रजाति 26
- ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण केंद्र 27
- प्रदेश में एक साथ 7 खेल अकादमियों की ऐतिहासिक शुरुआत 27
- 'साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल' 28
- स्कूल पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी की शिक्षाएँ 28
- छत्तीसगढ़ को मिला एक और मेडिकल कॉलेज 29
- राज्य में बिलासपुर वनवृत्त में सर्वाधिक तेंदू पत्ता का संग्रहण 29

The Vision

नोट :

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ क्वांटीफिएबल डाटा आयोग

चर्चा में क्यों ?

- 1 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की गणना हेतु छत्तीसगढ़ क्वांटीफिएबल डाटा आयोग का मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया और इस ऐप के माध्यम से गणना हेतु सर्वे का कार्य का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की गणना के लिये छत्तीसगढ़ क्वांटीफिएबल डाटा आयोग का गठन किया है। इसका कार्यालय राजधानी रायपुर के पीडब्ल्यूडी चौक, सागौन बंगला परिसर कटोरा तालाब में प्रारंभ हो चुका है।
- 'सीजीक्यूडीसी' नाम से इस मोबाइल ऐप को चिप्स द्वारा तैयार किया गया है।
- छत्तीसगढ़ क्वांटीफिएबल डाटा आयोग के सचिव बी.सी. साहू ने बताया कि मोबाइल ऐप को इंस्टाल करने के बाद ऐप में आवेदक को पंजीयन करना होगा।

ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवॉर्ड समारोह

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (नाचा) को शिकागो में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवॉर्ड समारोह में 'ऑर्गनाइजेशन ऑफ द ईयर' से नवाज़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह पहला पुरस्कार है, जो नाचा को यूएसए के वरिष्ठ राजनीतिक नेता डैनी के डेविस और एमेक्स लीडरशिप से प्राप्त हुआ है।
- छत्तीसगढ़ी एनआरआई एसोसिएशन ऑफ द ईयर के तेज विकास को देखते हुए इसका चयन किया गया है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किये जाने पर नाचा के सभी सदस्यों को बधाई दी।
- अमेरिका के वरिष्ठ सांसद (हाउस ऑफ रिप्रेंजेटेटिव्स) डैनी डेविस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिकन मल्टी एथनिक कोएलिशन और मल्टी एथनिक अमेरिकन टास्क फोर्स के साथ सामुदायिक वैश्विक पुरस्कारों को प्रायोजित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत के बाहर छत्तीसगढ़ विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये नाचा की शुरुआत 2017 में शिकागो में हुई थी और अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉन्ड है तथा राज्य को प्रोत्साहन देने एवं वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ समुदाय का समर्थन करने के लिये कई कार्यक्रमों की मेजबानी करता है।

नोट :

'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना'

चर्चा में क्यों ?

- 1 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' के लिये पंजीयन की शुरुआत की। इस योजना के लिये पंजीयन 1 सितंबर से 30 नवंबर, 2021 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हज़ार रुपए अनुदान देने के लिये 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' लागू की है।
- योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मज़दूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिये 6 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर शुरू की गई इस योजना में राज्य के भूमिहीन कृषि मज़दूर के अलावा चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा वनोपज संग्राहक परिवार भी लाभान्वित होंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' के माध्यम से प्रदेश के सर्वाधिक ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की जाएगी। न्याय योजना की यह नई कड़ी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी।
- मुख्यमंत्री बघेल ने योजना के लिये पात्र मज़दूर भाइयों और बहनों से अपना पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि इसी वर्ष उन्हें योजना का लाभ देने की शुरुआत हो जाएगी।
- 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना के पोर्टल (rggbkmny.cg.nic.in) में जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों ?

- 1 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इन स्वास्थ्य केंद्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन (दुर्ग) और चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गांधी चौक (बिलासपुर), मोरगा (कोरबा), रामटोला (राजनांदगांव) एवं चटौद (धमतरी) शामिल हैं।
- इन स्वास्थ्य केंद्रों का चयन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्चुअल निरीक्षण के बाद किया गया था।
- यह प्रमाण-पत्र अस्पतालों (स्वास्थ्य केंद्रों) को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये दिया जाता है।
- इसके साथ ही अब तक राज्य के 28 स्वास्थ्य केंद्रों को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट मिल गए हैं। इनमें 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 ज़िला अस्पताल शामिल हैं।

नोट :

'इन्वेस्टगढ़-छत्तीसगढ़' के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 2 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास कार्यालय में आयोजित 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना' के उद्घाटन समारोह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की औपचारिक घोषणा करते हुए 'इन्वेस्टगढ़-छत्तीसगढ़' के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, दुबई, मिस्र आदि देशों के विभिन्न निवेशक समुदायों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिये 27 जनवरी, 2022 से 1 फरवरी, 2022 तक नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' का आयोजन किया जाएगा।
- इसका आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्त्व में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसी फर्म मेसर्स एडुविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड नाम 'वेक्सपोइंडिया' इसकी मेज़बानी करेगा।
- इस परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने 'वेक्सपोइंडिया' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2022 के आयोजन के लिये नवा रायपुर में 'वेक्सपोइंडिया' को मुफ्त स्थान प्रदान करेगी।
- 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' कार्यक्रम के आयोजन के लिये 'वेक्सपोइंडिया' द्वारा एक विस्तृत परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है। परियोजना की पूरी लागत सरकार के सहयोग से प्रायोजकों के माध्यम से कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।
- इस परियोजना का कुल बजट लगभग 107 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस परियोजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से राज्य में 50 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट दुनिया के अग्रणी निवेशक समुदायों, कंपनियों, व्यापारिक नेताओं, राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय उद्योगपतियों को एक मंच पर इकट्ठा होने का अवसर प्रदान करेगा और इससे राज्य के उद्योगपतियों को भी मदद मिलेगी। यह आयोजन औद्योगिक विकास को गति देगा और राज्य में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करेगा।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस (IACP) अवॉर्ड 2021

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था आईएसीपी (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस) ने छतीसगढ़ के कोरिया ज़िले के एसपी संतोष कुमार सिंह को 'आईएसीपी अवार्ड 2021' से सम्मानित करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- संतोष सिंह को यह अवॉर्ड '40 अंडर 40' कैटेगरी में दिया जाएगा। यह विश्व के 40 वर्ष से कम आयु के ऐसे पुलिस अधिकारी को दिया जाता है, जिसने बेहतर नेतृत्त्व क्षमता के साथ पुलिसिंग कार्यों में नए प्रयोगों और अच्छे कार्यों से परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।
- एसपी संतोष कुमार सिंह का चयन उनके द्वारा पिछले 8 वर्षों में बेहतर पुलिसिंग और पुलिस की छवि सुधारने में किये गए कार्यों के आकलन के आधार पर किया गया है। पूर्व में छत्तीसगढ़ से डीआईजी ईओडब्ल्यू आरिफ शेख को यह अवॉर्ड प्राप्त हुआ है।
- इस बार विश्व के 6 देशों- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और भारत के 40 पुलिस अधिकारियों को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें देश से उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अमित कुमार का नाम भी शामिल है।

नोट :

- आईएसीपी प्रति वर्ष इस तरह के अवॉर्ड्स सितंबर माह में अपने वार्षिक समारोह में घोषित करता है। चयनित अधिकारियों को अक्टूबर 2022 में टेक्सास, अमेरिका में यह अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस (IACP) पुलिस नेताओं के लिये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली पेशेवर संघ है, जिसमें वर्तमान में विश्व के 165 देशों के 31,000 से अधिक पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1893 में हुई थी।

'अतिरिक्त आहार' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने राजनांदगांव ज़िले के मोहला से समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 'अतिरिक्त आहार' (Additional Diet) कार्यक्रम का वस्तुत: उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- सितंबर को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की है और इसे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (Mukhyamantri Suposhan Abhiyan) के तहत एक जन-आंदोलन के रूप में शुरू किया है।
- पोषण आहार के लिये एक जन-जागरूकता अभियान राज्य भर में शुरू किया जा रहा है और पोषण रथ बस्तर क्षेत्र के शहरों एवं कस्बों के साथ-साथ अंदरूनी इलाकों में भी जा रहे हैं।
- अभियान के तहत कुपोषण से प्रभावित बच्चों और महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें दवाईयाँ तथा पोषक आहारयुक्त किट वितरित की जाती है।
- पोषण आहार के प्रति लोगों को जागरूक करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, मितानिन और स्वयंसेवी संस्थाएँ अहम भूमिका निभा रही हैं।

शिक्षक स्मृति पुरस्कार और राज्य शिक्षक सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के 54 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 से और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित 54 शिक्षकों में से प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति-पत्र, शाल और 21 हज़ार रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई।
- इसके अलावा प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में दिये जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति-पत्र, शाल और 50 हज़ार रुपए की सम्मान निधि देकर सम्मानित किया गया।
- स्मृति पुरस्कारों की श्रेणी-
  - डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार- केशव राम वर्मा (प्रधान पाठक, पंचम दीवान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटापारा- बलौदाबाज़ार)
  - डॉ. गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार- चोवाराम वर्मा (व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसदा, सिमगा, बलौदाबाज़ार)

नोट :

- डॉ. मुकुटधर पांडेय स्मृति पुरस्कार- विजय कुमार शर्मा, (प्रधान पाठक, शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला कसेकेरा बागबाहरा, महासमुंद)
- डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार- कमलकिशोर ताम्रकार (शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उसरीजोर, गरियाबंद)

- इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के आमापारा स्थित आर.डी. तिवारी शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में आयोजित 'शिक्षा मड़ई' में कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिये नवाचार करने वाले राज्य के 20 शिक्षकों को सम्मानित किया।

राज्य के तीन जीआई टैग्ड उत्पादों पर डाक विभाग द्वारा जारी विशेष आवरण का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन जीआई टैग्ड उत्पादों- बस्तर का आयरन क्राफ्ट, वुडेन क्राफ्ट एवं जीराफूल चावल पर भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किये जा रहे विशेष आवरण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की तर्ज़ पर डाक विभाग द्वारा प्रदेश के 3 जीआई टैग्ड धरोहरों पर विशेष आवरण जारी कर देश भर में फैले डाक विभाग के विशाल नेटवर्क/फिलाटेली ब्यूरो एवं काउंटरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु यह पहल की गई है।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बस्तर आयरन क्राफ्ट एवं वुडेन क्राफ्ट (काष्ठ शिल्प) का प्रदेश की आदिवासी संस्कृति एवं इतिहास में एक अभिन्न स्थान रहा है और ये शिल्प देश-विदेश में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान भी बने हैं।
- साथ ही उन्होंने कहा कि जीराफूल चावल, प्रदेश का पहला एवं अभी तक का एकमात्र कृषि उत्पाद है, जिसे भारत सरकार द्वारा इसकी विशेष गुणवत्ता एवं पहचान के लिये जीआई टैग प्रदान किया गया है।
- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल भविष्य में भी राज्य के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक गौरव एवं धरोहरों का देश-विदेश में इसी प्रकार प्रचार-प्रसार में योगदान देते रहेंगे।

तीजा-पोरा तिहार

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजा-पोरा त्योहार के कार्यक्रम के अवसर पर समूह की महिला-बहनों को बड़ी सौगात देते हुए महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने की घोषणा की, ताकि वे पुन: ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियाँ आरंभ कर सकें।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही महिला कोष से महिला समूहों को प्रति वर्ष दिये जाने वाले ऋण के बजट में भी 5 गुना वृद्धि की घोषणा करते हुए महिला कोष के बजट की राशि दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह घोषणा राज्य में न्याय की एक कड़ी को और आगे बढ़ाने के रूप में देखी जा रही है। इससे स्व-सहायता समूहों से जुड़ी लाखों बहनों के सिर से 12 करोड़ 77 लाख रुपए के कर्ज़ का बोझ उतर जाएगा।
- महिला समूहों पर बकाया कालातीत ऋण की माफी से समूहों से जुड़ी लगभग एक लाख महिलाएँ नये सिरे से अपनी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करने के योग्य हो जाएंगी और उन्हें इसके लिये सहजता से ऋण की उपलब्ध हो सकेगा।
- महिला समूहों को अब दो लाख रुपए की ऋण की पात्रता होने से वह स्व-रोज़गार एवं स्वावलंबन की गतिविधियों को और अधिक विस्तार देने में सक्षम होंगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

नोट :

पोषण रथ

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा तिहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न ज़िलों के भ्रमण के लिये रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- यह रथ विभिन्न ज़िलों के विभिन्न गाँवों में भ्रमण कर पोषण का संदेश देगा। रथ में सुपोषण पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इसी के साथ मुख्यमंत्री बघेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पोषण प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर कुपोषण रहित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिये प्रतिबद्धता जताई।
- विभाग सचिव डॉ. कंगाले ने बताया कि इस रथ के माध्यम से रायपुर ज़िले में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी ऑडियो, वीडियो संदेशों का प्रसारण किया जाएगा।
- अन्य ज़िलों में भी पोषण रथ के माध्यम से विभिन्न स्थानों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे जनसमुदाय के मध्य फैसिलिटेटर द्वारा वीडियो प्रदर्शन उपरांत उपयोगी जानकारी दी जाती है।
- वीडियो मुख्यत: कुपोषण, पौष्टिक आहार, एनीमिया, स्तनपान, स्वच्छता, गर्भवती महिला की देखभाल, ऊपरी आहार पर आधारित है, जिसमें दृश्य-श्रव्य माध्यम का उपयोग करते हुए रोचक तरीके से स्वास्थ्य पोषण संबंधी जानकारी अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाए जाने का प्रयास है।

हर ज़िले में हिन्दी मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव (शिक्षा) डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी ज़िला कलेक्टरों को प्रत्येक ज़िले में एक हिन्दी माध्यम के स्कूल की पहचान कर इसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल की तर्ज़ पर प्रत्येक ज़िले में एक हिन्दी माध्यम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की थी।
- उन्होंने यह घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर रायपुर के अमापारा में स्वामी आत्मानंद आर.डी. तिवारी शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय के उद्घाटन के बाद की थी।
- प्रमुख सचिव (शिक्षा) ने ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि हेरिटेज स्कूलों का बाहरी स्वरूप नहीं बदला जाना चाहिये और केवल उन्नत प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों के लिये संशोधन किया जाना चाहिये।

'हथकरघा एवं हस्तशिल्प' प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों ?

- 7 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने दुर्ग ज़िले के भिलाई में स्थित सतनाम भवन में सातदिवसीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी 13 सितंबर तक चलेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस प्रदर्शनी का आयोजन ज़िला हथकरघा कार्यालय, दुर्ग द्वारा किया जा रहा है।
- इस प्रदर्शनी में बुनकरों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किये गए राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों सहित छत्तीसगढ़ राज्य की ढोकरा हस्तशिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बाँस शिल्प, गोदना शिल्प, शीसल शिल्प, टेराकोटा शिल्प, भित्ति चित्र, पत्थर शिल्प, कौड़ी शिल्प, तूंबा शिल्प और हथकरघा वस्त्रों में कोसा सिल्क, टसर सिल्क, कॉटन के ड्रेस मटेरियल, साड़ियाँ, दुपट्टे, चादर, बेडशीट तथा खादी वस्त्रों और ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित सामग्रियों के स्टॉल लगाए गए हैं।
- प्रदर्शनी में विभिन्न ज़िलों के लगे स्टॉलों की विभिन्न कलाकृतियों में धान के पैरा से बनी जांजगीर की कलाकृति, धान के पैरे से पिरोई गईं डॉ. भीमराव अंबेडकर, महावीर स्वामी और गणेशजी की आकर्षक कलाकृतियाँ प्रमुख हैं।
- इस अवसर पर गुरु रुद्रकुमार ने सभी हथकरघा वस्त्र एवं हस्तशिल्प कला के स्टॉलों की सराहना की और इसे अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को जीवित रखने का माध्यम बताया।
- उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलता है और उनकी कला तथा उनके द्वारा तैयार किये गए उत्पाद को बेहतर बाज़ार भी उपलब्ध होता है। इससे कारीगरों और शिल्पियों को अपनी अभिव्यक्ति को कला के माध्यम से व्यक्त करने में सहायता मिलती है तथा उनका हौसला बढ़ता है और वे दोगुने उत्साह से काम करते हैं।

'मोर ज़िम्मेदारी' अभियान

चर्चा में क्यों ?

- 7 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय से यूनिसेफ और एकता परिषद सहित अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चलने वाले जागरूकता अभियान 'मोर ज़िम्मेदारी' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री सिंहदेव ने इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को कोविड व्यवहार और वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करने हेतु मोर ज़िम्मेदारी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- सिंहदेव ने कहा कि यूनिसेफ, एकता परिषद एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्रदेश में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन व कोरोना व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान एक सराहनीय पहल है।
- यूनिसेफ के माध्यम से राज्य के 20 ज़िलों के दुर्गम 600 गांवों में इनके वालेंटियर घर-घर जाकर कोविड वैक्सीनेशन और संक्रमण से बचाव के लिये लोंगों को जागरूक करेंगे।
- उन्होंने कोविड टीका के महत्त्व के साथ-साथ ग्रामीणों को किसी प्रकार की अफवाह में न पड़ने के लिये भी जागरूक करने को कहा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने पर बल दिया कि जिन्हें प्रथम डोज लग चुकी है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में टीका की दूसरी डोज लग जाए।
- उन्होंने कोरोना से सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिये सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। कार्यक्रम में यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ हेड जॉब जाकरिया, एकता परिषद के रमेश शर्मा सहित वालेंटियर उपस्थित थे।

'एकीकृत किसान पोर्टल' लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

- 8 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में एकीकृत किसान पोर्टल https:\\kisan.cg.nic.in लॉन्च किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने एकीकृत किसान पोर्टल को लॉन्च करते हुए किसानों को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस पोर्टल से किसानों के लिये अपना पंजीयन कराना आसान हो जाएगा। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिये उन्हें एक बार ही पंजीयन कराना होगा।
- इस पोर्टल को कृषि विभाग के सहयोग से एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है।
- एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो-कुटकी, रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा।
- कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कृषि विभाग की सचिव डॉ. एम. गीता ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिये किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया का इस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण किया गया है, इससे विभिन्न योजनाओं के लिये किसानों का सुगमतापूर्वक पंजीयन हो सकेगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग में आसानी होगी। इस पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को आवश्यकतानुसार कैरी फार्वर्ड भी किया जा सकेगा।
- एकीकृत पोर्टल को भुंईयां (Bhuiyan) पोर्टल से लिंक किया गया है। इस पोर्टल में भूमि विवरण एवं गिरदावरी के आँकडों का भुंईयां पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन होगा तथा सटीक एवं त्वरित डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। किसानों की ज़मीन के भौतिक सत्यापन तथा योजनाओं के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की गणना में भी पोर्टल से आसानी होगी।
- वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारक, ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन समिति के पंजीयन हेतु विकसित पोर्टल को एकीकृत पोर्टल से लिंक किया गया है, ताकि आवेदकों को पंजीयन हेतु सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान किया जा सके।

'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 8 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' के प्रतीक चिह्न (लोगो) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मज़दूर परिवारों को 6 हज़ार रुपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी।
- इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के उन कृषि मज़दूर परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके पास खेती के लिये भूमि नहीं है मगर वे किसी न किसी प्रकार से कृषि कार्यों से जुड़े हैं।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई, 2021 को विधानसभा में इस योजना के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित किया था।
- राज्य सरकार का दावा है कि यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके लिये राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- इस योजना के लिये पंजीयन का कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा।

नगरीय निकाय: महिलाओं को 50% आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

- 8 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायतों की तरह ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिये सहमति दे दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह सहमति दी गई।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के संबंध में सभी राज्यों से अभिमत मांगा था।
- राज्यों की राय के बाद केंद्र सरकार इस संबंध में अंतिम पैसला लेगी।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण लागू है, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिलाओं को अभी 33% ही आरक्षण दिया जा रहा है।

बाजरा मिशन शुरू, IIMR के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य को बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से 'बाजरा मिशन'की औपचारिक शुरुआत की। इस मिशन के तहत भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Millet Research- IIMR), हैदराबाद ने राज्य के 14 ज़िलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- मिशन के तहत आईआईएमआर और राज्य के कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर ज़िलों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।
- मिशन के तहत किसानों को छोटी अनाज फसलों का सही मूल्य, विशेषज्ञों की इनपुट सहायता विशेषज्ञता मिलेगी।
- IIMR किसानों को तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, बीज बैंक स्थापित करने मंय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- बाजरा मिशन राज्य के वन क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि करेगा तथा छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी देगा।

बलरामपुर ज़िले के स्काउट-गाइड के छात्र राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य आयुक्त और संसदीय सचिव विनोद सेवालाल चंद्राकर के नेतृत्व में राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह का आयोजन राज्यपाल दरबार हॉल, रायपुर में किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मान समारोह में बलरामपुर ज़िले के स्काउट देव नारायण नेटी, राजकमल गुप्ता, रजनीश कुमार सिंह, सूर्यदेव कुशवाहा को राज्यपाल अनुसुइया उईके द्वारा राज्यपाल प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
- बलरामपुर ज़िले के शिक्षा अधिकारी बी.एक्का एवं स्काउट-गाइड के समस्त पदाधिकारियों के निरंतर प्रयास से बलरामपुर ज़िले के बच्चों को पहली बार राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- स्काउट-गाइड ज़िला संगठन आयुक्त जयपाल विश्वकर्मा ने बताया कि स्काउट-गाइड को उत्कृष्ट कार्यों के लिये हमेशा शासन-प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है और इस वर्ष की भाँति आने वाले वर्षों में भी स्काउट-गाइड के छात्रों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित कराने का प्रयास किया जाएगा।

नोट :

बस्तर: 'द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन'

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2021 को कोलकाता में आयोजित देश के सबसे बड़े टूरिज़्म ट्रेड फेयर में बस्तर को 'द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में 10 से 13 सितंबर तक आयोजित टीटीएफ मेले में विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा बस्तर विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा।
- यह अवॉर्ड टूरिज़्म फेयर में बस्तर के सहायक कलेक्टर सुरूचि सिंह के नेतृत्त्व में पर्यटन प्रतिनिधिमंडल ने ग्रहण किया।
- इस मेले में लगाए गए स्टॉल में बस्तर के पर्यटन, संस्कृति एवं कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है।
- मेले में देश-दुनिया से कलकत्ता पहुँचे टूर प्लानर और ट्रेवल एजेंट्स को 'द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन' पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया।
- इस मेले में आमचो बस्तर पर्यटन व स्थानीय कला संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिये बस्तर जिला प्रशासन से आमचो बस्तर पर्यटन समिति की चौदह सदस्यीय टीम शामिल हुई।
- इन सदस्यों को प्रमुख पर्यटन स्थलों चित्रकोट, तीर्था, बीजाकासा, कोसरटेड़ा, मादरकोंटा, महेंद्रीघूमर, तामड़ाघूमर, मिचनार, तीरथगढ़, टोपर, माँझीपाल समेत अन्य पर्यटन स्थलों से चुना गया था।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर देश-विदेश के सैलानियों को आकर्षित करने और बस्तर की कला संस्कृति को पर्यटन नक्शे पर उभारने के लिये विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है।
- बस्तर में पर्यटन रोज़गार ट्रेनिंग, पर्यटक ट्रेकिंग, रैपलिंग, पैरामोटर, कैंपिंग, बस्तरिया व्यंजनों की उपलब्धता, टूरिस्ट गाइड सुविधा, एस. टी.एफ कैंप, कोसारटेंडा बांध, इको रिसोर्ट समेत अनेक पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।

कोटेश्वर धाम में औषधीय प्रसंस्करण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- 11 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी ज़िले के कोटेश्वर धाम में औषधीय प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने ज़िले के कोटेश्वर धाम में वैद्यराज (पारंपरिक चिकित्सक) सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।
- इसके साथ ही उन्होंने कोटेश्वर धाम में वैद्यों के लिये विश्राम गृह तथा 4 हेक्टेयर क्षेत्र में धान खरीद केंद्र, स्टॉप डैम और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे के निर्माण की भी घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वैद्यों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण करने का काम शुरू कर दिया है। वैद्यराज अपने क्षेत्र में औषधीय पौधे उगा सकते हैं, जिसके लिये सरकार उन्हें सहायता प्रदान करेगी।
- उन्होंने कहा कि सतधारा में स्टॉप डैम बनाया जाएगा और कोटेश्वर को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट :

छत्तीसगढ़ में खुलेगी बैडमिंटन अकादमी

चर्चा में क्यों ?

- 13 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में जल्द ही बैडमिंटन अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने, खेल सुविधाओं के विकास और खेल प्रतिभाओं को निखारने से संबंधित विभिन्न खेल संघों और खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान की।
- उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं में सुधार के लिये छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। जल्द ही निकाय में खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि प्रमुख उद्योगों को स्टेडियम के रख-रखाव और खिलाड़ियों के लिये खाने-पीने की व्यवस्था की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही उद्योगों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।
- मुख्यमंत्री ने प्रतिभाओं को निखारने के लिये उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने पर ज़ोर दिया।
- बघेल ने व्यावसायिक और औद्योगिक समूहों से राज्य में खेलों को प्रोत्साहन हेतु योगदान देने का अनुरोध किया।

अब छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम

चर्चा में क्यों ?

- 13 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में वर्धा की तरह एक सेवाग्राम स्थापित करने के लिये लगभग 100 एकड़ भूमि निर्धारित करने की बात की।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्नित करेगा और महात्मा गांधी की 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा को बनाए रखेगा।
- मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को 2 अक्तूबर से पहले एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- उन्होंने कहा कि ग्राम सुधार के काम को आगे बढ़ाने के लिये सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। सेवाग्राम एक ऐसा स्थान होगा, जहाँ आगंतुक स्थानीय कला और शिल्प के साथ-साथ व्यंजनों के बारे में जान सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचितों के लिये वृद्धाश्रम और स्कूल भी स्थापित किये जाएँ गे। इनमें एक ओपन थिएटर भी होगा।

स्थानीय निवासियों की परिभाषा में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2021 को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के 'स्थानीय निवासियों' की परिभाषा में परिवर्तन के संबंध में शासन के सभी विभागों को परिपत्र जारी कर दिया गया। परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने 'स्थानीय निवासियों' की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी है, जिसके अनुसार "अब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।"

नोट :

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों, समस्त कलेक्टरों, ज़िला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा 17 जून, 2003 को जारी संदर्भित परिपत्र में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी गई है।

प्रदेश का पहला स्टील ब्रिज

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले के कुआकोंडा ब्लॉक में करमतपारा नाले पर प्रदेश का पहला स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। हालाँकि इस पर अभी आवागमन शुरु नहीं किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि कुआकोंडा-मैलावाडा के बीच बना यह ब्रिज केवल 20 दिनों में तैयार हुआ है।
- इस तरह के 6 अन्य ब्रिज ज़िले के 3 ब्लॉकों (कटेकल्याण, गीदम तथा कुआकोंडा) के 6 गाँवों- दुधिरास, कोरीरास, बड़ेगुडरा, हिड़पाल, कासोली और नकुलनार में बनेंगे।
- इन ब्रिजों के बनने से इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को बरसात के दिनों में आवागमन में होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ स्टील के ब्रिज बनाने में सुरक्षाबलों के कैंपों की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। स्टील के ब्रिज आसानी से और कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं।

छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 16 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार की ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम 'आभार आपकी सेवाओं का' को सरकारी सेवा वितरण के लिये 'ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी' श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 'एलेट्स इनोवेशन अवॉर्ड' (Elets Innovation Award) से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक, सीईओ और प्रधान संपादक डी. रवि गुप्ता ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह में छत्तीसगढ़ के ट्रेजरी अकाउंट्स एंड पेंशन के निदेशक नीलकंठ टीकाम को यह अवॉर्ड प्रदान किया।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के पेंशनरों के पेंशन मामलों के त्वरित निवारण के लिये मई 2018 से राज्य में 'आभार आपकी सेवाओं का' ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था।
- यह एक एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में ई-गवर्नेंस की अवधारणा के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- इस व्यवस्था के लागू होने के फलस्वरूप प्रथम पेंशन भुगतान हेतु पेंशनरों की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज़ (सर्विस बुक को छोड़कर) ऑनलाइन जमा किये जाते हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं। बैंकों को पेंशन के भुगतान के लिये सभी दस्तावेज़ भी कोषागारों द्वारा ऑनलाइन बैंक को भेजे जाते हैं।

नोट :

- पेंशनभोगी पेंशन विवरण की स्थिति जानने के लिये पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है और यहाँ तक कि ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकता है।
- साथ ही पेंशनर हेतु ई-कोष लाईट ऐप के पेंशनर कॉर्नर में पेंशनभोगियों को जारी किये गए पहचान-पत्र की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा है।
- इस प्रणाली से अब तक कुल 27,231 पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं।

हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ-साथ आईटीआई व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2021 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ-साथ आईटीआई व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग ज़िले के पाटन के स्वामी आत्मानंद स्कूल से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में स्कूली शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के लिये तैयार किये गए इस पाठ्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत की।
- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गए इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ आईटीआई कोर्स की पढ़ाई भी विद्यार्थी कर सकेंगे।
- इस पाठ्यक्रम में 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई का प्रमाण-पत्र भी मिलेगा। विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं का प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया जाएगा, जिससे वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकते हैं और आईटीआई का प्रमाण-पत्र भी मिलेगा, जिससे वे रोज़गार प्राप्त कर सकेंगे। दोनों कोर्स एक साथ चलेंगे।
- मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छात्रों के लिये वेल्डर ट्रेड और छात्राओं के लिये स्टेनोग्राफी हिन्दी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह पाठ्यक्रम दो वर्ष का होगा। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान दो वर्ष में यह पाठ्यक्रम पूरा होगा।
- स्कूली स्तर पर ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहे छोटे और बड़े उद्योगों में रोज़गार प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही वे स्व-रोज़गार भी कर सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इस रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाएगा और ज़रूरत के अनुसार नए ट्रेड इसमें शामिल किये जा सकेंगे।
- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रदेश में 172 अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल प्रारंभ किये गए हैं। इसी तरह बहुउद्देशीय हिन्दी माध्यम स्कूलों को भी स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूलों के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय दर से आधी

चर्चा में क्यों ?

- 16 सितंबर, 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय दर की तुलना में मात्र आधी है। छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी की दर 3.8 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय बेरोज़गारी दर 7.6 प्रतिशत है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों के अनुसार बेरोज़गारी दर आंध्र प्रदेश में 6.5 प्रतिशत, बिहार में 13.6, राजस्थान में 26.7, तमिलनाडु में 6.3, उत्तर प्रदेश में 7, उत्तराखंड में 6.2, दिल्ली में 11.6, गोवा में 12.6, असम में 6.7, हरियाणा में 35.7, जम्मू-कश्मीर में 13.6, केरल में 7.8, पंजाब में 6, झारखंड में 16 तथा पश्चिम बंगाल में 7.4 प्रतिशत है।

नोट :

- छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति उक्त राज्यों से कई गुना बेहतर है। यह राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन का परिणाम है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 74 फीसद आबादी गाँवों में निवास करती है तथा उसके जीवनयापन का आधार कृषि और वनोपज है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्त्व में राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास के चलते गाँवों की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। गाँवों में रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं।
- कोरोना संक्रमण काल के दौरान मनरेगा के कामों को बेहतर तरीके से संचालित करने के साथ ही धान खरीदी, लघु वनोपज के संग्रहण, खरीदी एवं प्रोसेसिंग की व्यवस्था को भी चालू रखा गया, जिससे गाँवों में लोगों को निरंतर रोज़गार सुलभ हुआ है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गाँव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में मदद की है।
- सरकार की उक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों, मनरेगा के श्रमिकों, वनोपज संग्राहकों को सीधे मदद मुहैया कराई गई। इसका परिणाम यह रहा कि मार्केट में कैश फ्लो और रौनक कायम रही, जिससे राज्य में बेरोज़गारी दर को नियंत्रित करने में मदद मिली है।

'न्याय जनता के द्वार अभियान'

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश भर में 'न्याय जनता के द्वार अभियान' प्रारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अभियान की शुरुआत करते हुए दो लीगल एड क्लिनिक बसों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर बिलासपुर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा सहित हाईकोर्ट के सभी जजों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें राज्य के दूरस्थ अंचलों में पहुँचकर लोगों को न्याय के लिये जागरूक करेंगी।
- हाईकोर्ट परिसर के अलावा प्रत्येक ज़िले में भी एक-एक लीगल एड क्लिनिक बस विशेष टीम के साथ रवाना की गई है। यह टीम कम-से-कम 100 गाँवों में जाकर न्याय के लिये लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी।
- इस अवसर पर जस्टिस मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गाँव-गाँव में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना है।
- इसके तहत हाट बाज़ार जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अशिक्षित लोगों को न्याय और विधिक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें और न्याय पाने के लिये स्वयं न्यायालयों में जाएँ।
- 100 से अधिक शिविरों के दौरान विशेष रूप से उन सभी महत्त्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो स्वस्थ समाज के लिये आवश्यक हैं। इनमें गुड टच बैड टच, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के अधिकार, खेलों में भाग लेने की प्रेरणा, साइबर अपराध के प्रति सचेत करना, साइबर कानून के प्रति जागरूक रहना शामिल हैं।
- साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के कानून, भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी कानून, पॉक्सो एक्ट की गंभीरता, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और समान वेतन का अधिकार जैसे अनेक विषयों की जानकारी दी जाएगी।
- इसके अलावा राज्य में विधिक सहायता और आपसी समझौते से परिवादों के निराकरण के लिये लगाई जाने वाली लोक अदालतों की जानकारी भी दी जाएगी और विवादों के निपटारे के लिये लोक अदालत शिविरों का लाभ उठाने की अपील की जाएगी।
- ग्राम स्तर पर 'हमार अंगना योजना' के अंतर्गत घरेलू हिंसा से जुड़े कानून की जानकारी दी जाएगी। 'कर्त्तव्य अभियान' के तहत संविधान के अनुच्छेद 51 को लेकर जागरूक किया जाएगा।

नोट :

- एमएससीटी के मामले, मोटर व्हीकल एक्ट के नए अधिनियम, कोरोना वायरस से बचाव के लिये वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता के अधिकार, धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता तथा नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी जाएगी। नालसा के यूट्यूब चैनल के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिये भी जागरूक किया जाएगा।

NQAS के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में मिला द्वितीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2021 को रोगी सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के क्रियान्वयन में पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार प्रदेश में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के क्रियान्वयन में ज़िला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दोनों ही श्रेणी में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के बीच किये गए प्रदर्शन हेतु दिया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्य के अस्पतालों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और मरीज़ों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण के बाद संस्था का आंतरिक तथा राज्यस्तरीय मूल्यांकन, सेवा प्रदाय आडिट और पेशेंट संतुष्टि सर्वे की प्रक्रिया की जाती है।
- भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के चिह्नांकित अस्पतालों का ओपीडी, आईपीडी, लेबोरेटरी, प्रसव कक्ष, आपातकाल सेवा, रेडियोलॉजी, फार्मेसी व स्टोर, जनरल एडमिन, ऑपरेशन थिएटर एवं एनबीएसयू जैसे मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक छत्तीसगढ़ के कुल 28 अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों (जिनमें 7 ज़िला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं) को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान किये जाने पर गुणवत्ता प्रमाण-पत्र दिया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के संकट काल में भी राज्य के 16 सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। वहीं वर्ष 2019-20 व वर्ष 2018-19 में कुल 6-6 अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रमाण-पत्र दिये गए।

राजीव युवा मितान क्लब योजना

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान राज्य में 'राजीव युवा मितान क्लब योजना' का शुभारंभ किया तथा क्लब के गठन एवं संचालन के लिये ज़िलों को 19.43 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किये जाएंगे। क्लबों को वर्ष भर में 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
- राजीव युवा मितान क्लब के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रत्येक क्लब को प्रत्येक तीन माह में 25 हज़ार रुपए के मान से एक साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिये एक लाख रुपए दिये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के युवा भारत के सपने को साकार करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की गई है।

नोट :

- इसका उद्देश्य राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हें संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है।
- मुख्यमंत्री कहा कि युवा शक्ति, राज्य के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण पूंजी है। राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने और उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का यह क्रांतिकारी कार्यक्रम है। युवाओं के माध्यम से छतीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण, खेल को आगे बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने और लोगों को इसका लाभ दिलाने में मदद मिलेगी।
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग सचिव एन.एन. एक्का ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब का ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर गठन किया जाएगा। क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत होगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी।
- योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय समिति का गठन होगा। राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। जिला एवं अनुविभाग स्तर पर भी समितियाँ गठित की जाएंगी। ज़िलों के प्रभारी मंत्री ज़िलास्तरीय समिति के संरक्षक होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 जनवरी, 2020 को छत्तीसगढ़ युवा उत्सव के समापन समारोह में राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा की थी।

तृतीय लिंग समुदाय के लिये नीति

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तृतीय लिंग समुदाय के 13 नव-नियुक्त पुलिस आरक्षकों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई व शुभकामनाएँ दीं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सभी जाति, वर्ग, समुदाय और लिंग के व्यक्तियों के हितों एवं उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिये काम कर रही है। सामाजिक सद्भाव और समरसता को आगे बढ़ाना राज्य सरकार की नीति है।
- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने राज्य के तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिये पॉलिसी बनाई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य ने तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस साल के बजट में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सह पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिये 76 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।
- राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय के डाटा संधारण के लिये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सर्वेक्षण में 2 हज़ार 919 तृतीय लिंग के व्यक्ति चिह्नांकित किये गए हैं, जिनमें से 1,025 व्यक्तियों को पहचान-पत्र जारी किया गया है, जो राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड इत्यादि के लिये मान्य है।

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी, धार्मिक नगरी रतनपुर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ कि धार्मिक और पौराणिक नगरी रतनपुर को देश एवं दुनिया के पर्यटकों के सामने लाने तथा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु राज्य शासन कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और राज्य शासन ने बीते दिनों रतनपुर व आसपास के पर्यटन स्थलों का जायजा लिया।

नोट :

- पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के बाद राजा मोरध्वज और रत्नदेव की इस नगरी को दुनिया भर के पर्यटक अब करीब से देख सकेंगे।
- पर्यटकों के लिहाज से यहाँ की विशेषता और कला को उभारा जाएगा, ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक महत्त्व के महल व किले को सँवारा जाएगा।
- तालाबों कि नगरी के नाम से प्रसिद्ध रतनपुर की सबसे बड़ी खाशियत ये है कि यहाँ कई सौ साल पुराने 200 तालाबों की ऐसी श्रृंखला है, जिसके कारण यहाँ अब तक अकाल नहीं पड़ा। तालाबों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि बारिश के दिनों में एक तालाब के भर जाने पर पानी दूसरे तालाब में पहुँचता है।
- उल्लेखनीय है कि बिलासपुर ज़िले में स्थित यह नगरी आदिशक्ति माँ महामाया देवी के मंदिर के लिये प्रसिद्ध है। इस पवित्र पौराणिक नगरी का प्राचीन एवं गौरवशाली इतिहास है। इसे 'चतुर्युगी नगरी' भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि इसका अस्तित्व चारों युगों में विद्यमान रहा है।
- त्रिपुरी के कलचुरि राजा रत्नदेव प्रथम ने सर्वप्रथम रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था और बाद के कलचुरि राजाओं ने इसी राजधानी से दीर्घकाल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था।
- महामाया मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। मंदिर के भीतर महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी स्वरूप देवियों की प्रतिमाएँ विराजमान हैं।
- मान्यता है कि रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमारी शक्ति पीठ का नाम दिया था, जिसके कारण माँ के दर्शन से कुँवारी कन्याओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ हज़ारों की संख्या में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण में अव्वल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जारी 'द ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राईफेड)' के आँकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम तिमाही माह अप्रैल से जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- ट्राईफेड द्वारा जारी किये गए आँकड़ों के अनुसार राज्य में इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि के 2 लाख 77 हज़ार 958 क्विंटल लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जो देश में इस दौरान 93 करोड़ रुपए मूल्य के कुल संगृहीत लघु वनोपजों का 88.36 प्रतिशत है।
- इनमें 40.90 करोड़ रुपए की राशि के 113614 क्विंटल इमली (बीज सहित) तथा 27.59 करोड़ रुपए की राशि के 1,37,946 क्विंटल साल बीज का संग्रहण किया गया है। इसी तरह 4.15 करोड़ रुपए की राशि के 6,595 क्विंटल फूल इमली, 2.92 करोड़ रुपए की राशि के 2390 क्विंटल चिंरौजी गुठली तथा 1.78 करोड़ रुपए की राशि के 10,493 क्विंटल बहेड़ा का संग्रहण शामिल है।
- इस दौरान माहुल पत्ता, नागरमोथा, भेलवा, बहेड़ा कचरिया, धवई फूल (सूखा), हर्रा कचरिया, पुवाड़ (चरोटा), बेल गूदा, सतावर (सूखी), कुसुम बीज, फूल झाड़ू, रंगीनी लाख, वन तुलसी, फूल इमली, जामुन बीज (सूखा), वन जीरा, इमली बीज, आँवला बीजरहित, कुसुमी लाख, कुल्लू गोंद, महुआ बीज, करंज बीज तथा बायबडिंग का संग्रहण हुआ है।
- इसके अलावा पाताल कुम्हड़ा (बेदारी कंद), तिखुर, सवई घास, कोरिया छाल, छिन्द घास, आँवला (कच्चा), काँटा झाड़ू, कुटज छाल, अडुसा पत्ता, इंद्रजौ बीज, सफेद मूसली, पलाश फूल आदि का भी संग्रहण किया गया है।

नोट :

- राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 52 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। जिनमें साल बीज, हर्रा, इमली बीज सहित, चिरौंजी गुठली, महुआ बीज, कुसुमी लाख, रंगीनी लाख, काल मेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेल गूदा, शहद तथा फूल झाड़ू, महुआ फूल (सूखा) शामिल हैं। इसके अलावा जामुन बीज (सूखा), कौंच बीज, धवई फूल (सूखा), करंज बीज, बायबडिंग और आँवला (बीज सहित) तथा फूल इमली (बीजरहित), गिलोय तथा भेलवा, वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया तथा नीम बीज शामिल हैं।
- इसी तरह कुसुमी बीज, रीठा फल (सूखा), शिकाकाई फल्ली (सूखा), सतावर जड़ (सूखी), काजू गुठली, मालकांगनी बीज, माहुल पत्ता, पलास (फूल), सफेद मूसली (सूखी), इंद्रजौ, पाताल कुम्हड़ा तथा कुटज (छाल), अश्वगंधा, आँवला कच्चा, सवई घास, काँटा झाड़ू, तिखुर, बीहन लाख-कुसमी, बीहन लाख-रंगीनी, बेल (कच्चा) तथा जामुन (कच्चा) शामिल हैं।
- राज्य सरकार द्वारा कुसुमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद की खरीदी में समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में होगी 10 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2021 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 10 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना के लिये मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है। इस आशय का पत्र मंत्रालय, महानदी भवन स्थित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के जिन स्थानों पर इन नवीन महाविद्यालयों की स्थापना को मंज़ूरी मिली है, वे हैं-
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय नागपुर (ज़िला- कोरिया)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय सन्ना (ज़िला- जशपुर)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा (ज़िला- कोरबा)
  - शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर (ज़िला- बलरामपुर)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय गोबरा-नवापारा (ज़िला- रायपुर)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागाँव सेक्टर-28 नवा रायपुर (ज़िला- रायपुर)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली (ज़िला- दुर्ग)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन (ज़िला- दुर्ग)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय सारागाँव (ज़िला- जांजगीर-चांपा)
  - शासकीय नवीन महाविद्यालय सूरजपुर (ज़िला- सूरजपुर)

प्रदेश में रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को मिली सैद्धांतिक सहमति

चर्चा में क्यों ?

- 23 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश मुकेश बघेल ने रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को राज्य में लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से भारत सरकार के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा ली गई बैठक में शामिल होते हुए यह सहमति दी।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिये अतिरिक्त समय-सीमा दिये जाने की मांग का समर्थन किया।
- इस बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के ऊर्जा मंत्री और दमन-दीव के प्रशासक भी शामिल हुए।
- रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी 53 लाख 50 हज़ार उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई है।
- इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रुपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

आयुष्मान के लिये छत्तीसगढ़ को मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 23 सितंबर, 2021 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में छत्तीसगढ़ ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित 'आरोग्य मंथन 3.0' में प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान किये।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा छह श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किये गए, जिनमें से चार श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में छत्तीसगढ़ ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
- छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर्स के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिये प्रथम स्थान मिला है।
- राज्य के प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।
- प्रदेश के सूरजपुर ज़िले के भैयाथान विकासखंड के कुसमुसा गाँव के चॉइस सेंटर संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैं।
- लैंगिक-समानता को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। योजना के माध्यम से प्रदेश की 3,20,661 महिलाओं को उपचार उपलब्ध कराया गया है।

19वीं स्टेग छत्तीसगढ़ राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2021

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष शरद शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ द्वारा 19वीं स्टेग छत्तीसगढ़ राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2021 का आयोजन 23 से 30 सितंबर तक बूढ़ापारा रायपुर स्थित स्प्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- शरद शुक्ला ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन 23 सितंबर को अंडर-19 बालक एवं बालिका एकल वर्ग खेल का आयोजन होगा।
- कोविड को ध्यान रखते हुए सभी वर्गों की एकल प्रतियोगिता का आयोजन अलग-अलग दिन किया जाएगा।

नोट :

- इस प्रतियोगिता के जूनियर बालक वर्ग में प्रथम वरीयता प्राप्त बिलासपुर के रोहन लालवानी एवं द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वरीयता प्राप्त: क्रमश: रायपुर के करण मल्होत्रा, प्रणय चौहान, रामजी कुमार हैं।
- बालिका वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में क्रमश: बिलासपुर की आर. देवांशी, अनन्या दुबे, सुष्मिता सोम व धमतरी की भुनेश्वरी हैं।
- प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर विमल नायर एवं सहायक मुख्य निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अभिनव शर्मा एवं अरुण बावरिया हैं।

वाणिज्य उत्सव

चर्चा में क्यों ?

- 21-22 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ राजधानी रायपुर में दो दिवसीय 'वाणिज्य उत्सव' संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ देश के निर्यात परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एवं यहाँ वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। यह वाणिज्य उत्सव राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा।
- मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य मंडप का भी उद्घाटन किया। जहाँ राज्य के प्रमुख निर्यातकों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही, उन्होंने 'बंबू द ग्रीन गोल्ड' पुस्तिका का विमोचन भी किया।
- कार्यक्रम के पहले दिन 'भारत में छत्तीसगढ़ राज्य एक उभरती आर्थिक शक्ति' सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रस्तुतीकरण दिये गए एवं बाँस आधारित उद्योगों की संभावनाओं व पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, न्यूट्रास्कुटिकल उद्योगों की स्थापना तथा राज्य से विभिन्न उत्पादों की निर्यात संभावनाओं की जानकारी दी गई एवं सफल निर्यातकों से चर्चा की गई।
- कार्यक्रम के दूसरे दिन 22 सितंबर को निर्यातक वर्कशॉप के दौरान निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय एवं नियामक बाधाओं एवं उनके निराकरण पर आधारित इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशन के तहत चर्चा की गई।
- उल्लेखनीय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की 75 साल की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करने के लिये देश के सभी ज़िलों में 'वाणिज्य उत्सव' का आयोजन किया जा रहा है।

कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर, कोंडागाँव और बस्तर ज़िले से आए आदिवासी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के 14 कोदो-कुटकी उत्पादक ज़िलों में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो-कुटकी की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ज़िलों के गोठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किये जाएंगे और प्रसंस्कृत कोदो की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी।
- कोदो-कुटकी का उत्पादन करने वाले ज़िलों में बस्तर संभाग के 7 ज़िले, सरगुजा संभाग के 5 ज़िले और राजनांदगाँव तथा कवर्धा ज़िले शामिल हैं।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर बस्तर संभाग में जहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल प्रारंभ हुए हैं, वहाँ हॉस्टल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे इन स्कूलों में दूर गाँवों से आने वाले बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी।

मुकुंद रेडियो द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मुकुंद रेडियो द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ का विमोचन किया। इस मोनोग्राफ में वर्ष 1952 से 2021 तक अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग छह दशकों का दृश्यात्मक दस्तावेज़ संकलित है।

प्रमुख बिंदु

- मुकुंद रेडियो के संचालक संजय मोहदीवाले ने बताया कि 1950 के दशक में स्थापित इस संस्थान में सभी राजनीतिक- सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सचित्र ब्यौरा रखा गया है।
- संस्थान में श्वेतश्याम दौर से लेकर आज के डिजिटल युग तक छत्तीसगढ़ अंचल में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली मशहूर हस्तियों की तिथिवार तस्वीरों की एक लघु दीर्घा मौजूद है। इन्हीं तस्वीरों के दस्तावेज़ को मोनोग्राफ की शक्ल में प्रकाशित किया गया है।
- मोनोग्राफ के आकल्पक व संपादक राजेश गनौदवाले ने बताया कि किताब में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, रविशंकर शुक्ल, मन्ना डे, पंकज उधास, बेगम अख्तर, जगजीत सिंह जैसी हस्तियों के छत्तीसगढ़ आगमन से लेकर मुख्यमंत्री बघेल के कार्यकाल के 2 वर्षों की चुनिंदा तस्वीरें शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने मोनोग्राफ की प्रति स्वहस्ताक्षरित कर शुभकामना संदेश दिया और कहा कि ऐसा फोटो दस्तावेज़ इकट्ठा करना, जिसमें प्रदेश में आई सभी शख्सियतों का रिकॉर्ड हो और उसे दशकों तक सहेज कर सिलसिलेवार रूप से प्रकाशित करना अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य है।

नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2021 को परिवार नियोजन कार्यक्रम के उप-संचालक डॉ. सत्यार्थी ने बताया कि पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है। इस दौरान प्रदेश में 4905 पुरुषों ने परिवार नियोजन के लिये नसबंदी कराई है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सत्यार्थी ने बताया कि पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 966, वर्ष 2018-19 में 72, वर्ष 2019-20 में 1695, वर्ष 2020-21 में 168 और वर्ष 2021-22 में 1349 पुरुषों ने नसबंदी कराई है।
- उन्होंने कहा कि नसबंदी पखवाड़ा के दौरान ग्राम स्तर से लेकर ज़िला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर लोगों में पुरुष नसबंदी के प्रति फैली भ्राँतियों व मिथकों को विभाग द्वारा दूर किया जाता है। ग्राम स्तर पर 'मोर मितान मोर संगवारी' चौपाल का आयोजन कर पुरुषों को नसबंदी कराने हेतु प्रेरित किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार और परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिये प्रदेशव्यापी पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाता है।
- पखवाड़ा दो चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण मोबिलाइजेशन सप्ताह के रूप में होता है, जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने एवं राज्य में एनएसवीटी कार्यक्रम को सुचारु ढंग से संचालित कर नसबंदी के लिये पुरुषों को जागरूक किया जाता है एवं 'मोर मितान मोर संगवारी' की थीम पर ग्राम स्तर पर आयोजित गोष्ठियों मं6 पुरुषों को नसबंदी हेतु प्रेरित किया जाता है। वहीं दूसरा चरण सेवा वितरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा नसबंदी कराने वालों को दो हज़ार रुपए एवं उत्प्रेरकों को 250 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

नोट :

देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक स्वर्गीय देवदास बंजारे की स्मृति में राज्यस्तरीय 'देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार' की स्थापना की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक शैली 'पंथी नृत्य' प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित तथा सम्मानित करना है।
- देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की नियमावली का प्रकाशन 10 सितंबर, 2021 को राज-पत्र में हो चुका है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 दिसंबर, 2020 को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर स्वर्गीय देवदास बंजारे की स्मृति में पंथी नृत्य पुरस्कार स्थापित किये जाने की घोषणा की थी।
- इस पुरस्कार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य अलंकरण समारोह में शामिल कर लिया गया है।
- पंथी नृत्य पुरस्कार के तहत 50 हज़ार रुपए की सम्मान राशि, प्रतीक चिह्न और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा पहले से ही 'देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार' स्थापित है, जो राज्य में प्रदर्शनकारी लोक शैली कला क्षेत्र के क्षेत्र अंतर्गत स्थापित है। देवदास बंजारे की स्मृति में यह राज्यस्तरीय दूसरा पुरस्कार केवल लोक शैली 'पंथी नृत्य' प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस प्रकार अब संस्कृति विभाग से दिये जाने वाले पुरस्कारों की संख्या अब 8 हो गई है।

कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की हल्दी व धनिया की नई प्रजाति

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2021 को कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान परियोजना की वार्षिक बैठक में रायगढ़ के वैज्ञानिकों के शोध से विकसित धनिया एवं हल्दी के नई प्रजातियों की राष्ट्रीय स्तर पर विमोचन हेतु पहचान की गई।

प्रमुख बिंदु

- इन प्रजातियों को केंद्रीय विमोचन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत दोनों प्रजातियों को बीज उत्पादन श्रृंखला में लाया जाएगा।
- धनिया की एक प्रविष्ठी को छत्तीसगढ़ राज्य धनिया-3 के नाम से शामिल किया जाएगा तथा देश के 10 प्रदेशों के लिये विमोचित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हल्दी की प्रविष्ठी को छत्तीसगढ़ राज्य हल्दी-3 के नाम से शामिल किया जाएगा और देश के 7 प्रदेशों के लिये विमोचित किया जाएगा। विमोचन के बाद इन प्रजातियों के बीज का विभिन्न वर्गों में उत्पादन भी किया जा सकेगा।
- इन प्रजातियों के प्रमुख प्रजनक वैज्ञानिक डॉ. श्रीकांत सांवरगावकर ने बताया कि धनिया एवं हल्दी की ये दोनों प्रजातियाँ किसानों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण एवं लाभदायक हैं, जो कि किसानों के बाज़ार के अनुरूप हैं। इनके उत्पादन से किसान ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रजातियों का उत्पादन ज़्यादा एवं गुणवत्ता अच्छी है। इनकी फसल अवधि प्रचलित प्रजातियों से थोड़ा कम है।
- परियोजना के प्रमुख अन्वेषक एवं कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. सिंह ने बताया कि इन दोनों प्रजातियों से छत्तीसगढ़ के ही नहीं, अपितु अन्य राज्यों के किसानों को भी इनका लाभ मिलेगा। इन प्रजातियों में रोगों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधकता अधिक है। इन प्रजातियों की उत्पादन लागत कम होने एवं उत्पादन अधिक होने से कृषकों को अधिक लाभ मिलेगा।

नोट :

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश में संचालित ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण केंद्रों (RSETI) की वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट, 2020-21 का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एजेंसी नेशनल एकेडमी ऑफ रूडसेटी, बंगलुरू द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है।
- सिंहदेव ने रिपोर्ट का विमोचन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 18 ज़िलों में संचालित ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को अनेक रोज़गारमूलक गतिविधियों का नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश भर में 302 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन कर 7003 युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार बैंक मित्र, सामान्य उद्यमिता विकास, मशरूम उत्पादन, पापड़ निर्माण, आचार निर्माण, मसाला निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, सिलाई तथा डेयरी फॉर्मिंग इत्यादि का स्वरोज़गार आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- इन केंद्रों में प्रशिक्षित लोगों में 95 प्रतिशत महिलाएँ हैं। सामाजिक समावेश के आधार पर अनुसूचित जनजाति के 36 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 46 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के चार प्रतिशत हितग्राहियों को इन केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।
- सिंहदेव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान मौजूद असेसमेंट एवं सर्टिफिकेशन शाखा के सहायक नियंत्रक अरुण कुमार सोनी को प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ज़रूरतमंद ग्रामीण युवाओं के लिये उनकी रुचि की विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये।

प्रदेश में एक साथ 7 खेल अकादमियों की ऐतिहासिक शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के खिलाड़ियों के लिये एक साथ 7 खेल अकादमियों की ऐतिहासिक शुरुआत की। इनमें से बिलासपुर में 4 तथा रायपुर में 3 खेल अकादमी विधिवत प्रारंभ हुईं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत वाली नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें मुख्य रूप से फुटबाल, कबड्डी, तीरंदाज़ी और एथलेटिक्स की अकादमी, दो खेल छात्रावास, एक तीरंदाज़ी प्रशिक्षण उपकेंद्र और एथलेटिक्स के लिये सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाज़ी, एथलेटिक्स और कबड्डी अकादमी तथा रायपुर में तीरंदाज़ी, बालिका फुटबाल एवं बालक-बालिका एथलेटिक्स अकादमी का शुभारंभ किया।
- बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाज़ी, एथलेटिक्स की बोर्डिंग एवं कबड्डी (बालिका) अकादमी तथा रायपुर में तीरंदाज़ी की बोर्डिंग, फुटबाल (बालिका) एवं एथलेटिक्स (बालक-बालिका) की डे- बोर्डिंग अकादमी में कुल 370 सीटें हैं, जिसमें 180 बोर्डिंग सीट एवं 190 डे-बोर्डिंग सीट शामिल हैं।

नोट :

- इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल परिसर में 9.20 करोड़ रुपए की लागत से बने 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड, 2.82 करोड़ की लागत से बालकों के लिये निर्मित 50 सीटर खेल छात्रावास, 4.75 करोड़ रुपए की लागत से बालिकाओं के लिये निर्मित 100 सीटर खेल छात्रावास तथा 4.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया।
- उन्होंने बिलासपुर में 4 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कबड्डी इंडोर हॉल, 15 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की गैलरी एवं पैवेलियन के निर्माण सहित वहाँ फ्लड लाईट लगाए जाने के कार्य की आधारशिला रखी।
- मुख्यमंत्री ने रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम परिसर में स्वर्गीय कोदूराम वर्मा स्मृति तीरंदाज़ी प्रशिक्षण अकादमी, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम परिसर कोटा में बालिकाओं के लिये फुटबाल अकादमी तथा बालक-बालिकाओं के लिये एथलेटिक्स अकादमी का भी शुभारंभ किया।

'साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल'

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस साल आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल का नामकरण छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष एवं आदिवासी संस्कृति में देवतुल्य साल वृक्ष के नाम पर 'साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल' रखने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में ट्राइबल फेस्टिवल के साथ ही राज्योत्सव की रूपरेखा तय की गई। राज्य शासन द्वारा 'साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल एवं राज्योत्सव' का संयुक्त रूप से पाँच दिवसीय आयोजन 28 अक्तूबर से लेकर एक नवंबर तक रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि साल छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। आदिवासी संस्कृति में साल वृक्ष को देवतुल्य मानकर पूजा जाता है। आदिवासी अंचल में धूमधाम से मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसलिये ट्राईबल फेस्टिवल का नामकरण 'साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल' किया गया है।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल का आयोजन, 31 अक्तूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर उनके कर्त्तव्य तथा आदिवासी जनजीवन पर परिचर्चा एवं गोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध वक्ता एवं विचारक शामिल होंगे।
- एक नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति, विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त लोगों एवं संस्थाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा।
- साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल एवं राज्योत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त लोगों से इंटरेक्शन, प्रदर्शनी, आदिवासी कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन, ट्राईबल क्राफ्ट मेला, कौशल उन्नयन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश-विदेश के कलाकार इस दौरान अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे।

स्कूल पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी की शिक्षाएँ

चर्चा में क्यों ?

- 28 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कहा कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षाओं को छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कक्षा 5 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चों को उनके अहिंसा संबंधी आदर्शों और सिद्धांतों से अवगत कराया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिये मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा का प्रबंध राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

नोट :

- इसमें शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गांधीजी की मंशा के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर गांधीजी के आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को पूरा करने के लिये स्कूली बच्चों को गाँव का भ्रमण कराकर सरकार की महत्त्वाकांक्षी सूराजी गाँव योजना के तहत नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
- इससे बच्चों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ जल और मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी मिल सकेगी और एक आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना को साकार किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ को मिला एक और मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल रायपुर में संचालित श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को 150 सीटों के लिये लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- मेडिकल कॉलेज के रूप में मान्यता मिलने के बाद इसमें इसी वर्ष एमबीबीएस के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
- श्री बालाजी हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. देवेंद्र नायक ने बताया कि अस्पताल में 1,000 बिस्तरों कि सुविधाएँ मिलेंगी।
- यह मेडिकल कॉलेज खुलने से क्षेत्र के छात्रों को अध्ययन के लिये एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा तथा ज़्यादा संख्या में डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी।
- गौरतलब है कि श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई, मेडिकल साइंसेज रायपुर के बाद यह राज्य का तीसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है।
- श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (SBIMS) श्री बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का एक हिस्सा है, जो 1050 बिस्तरों वाला (मध्य भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल समूह) आधुनिक और अत्याधुनिक तृतीयक देखभाल केंद्र है। इसका उद्घाटन 15 फरवरी, 2009 को हुआ था।

राज्य में बिलासपुर वनवृत्त में सर्वाधिक तेंदू पत्ता का संग्रहण

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य लघु वनोपज से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान समस्त 6 वनवृत्तों में से बिलासपुर वन के अंतर्गत सर्वाधिक 2 लाख 76 हज़ार 670 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष के दौरान तेंदू पत्ता संग्रहण सीजन में 522 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 13 लाख 5 हज़ार 710 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है। इसमें तेंदू पत्ता संग्राहकों को 110 करोड़ 21 लाख रुपए की संग्रहण राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।
- बिलासपुर वनवृत्त के अंतर्गत 110 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि के 2 लाख 76 हज़ार 670 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ। इनमें वनमंडलवार बिलासपुर में 29 हज़ार 715 मानक बोरा, मरवाही में 19 हज़ार 440 मानक बोरा, जांजगीर-चांपा में 3 हज़ार 763 मानक बोरा, रायगढ़ में 44 हज़ार 702 मानक बोरा, धरमजयगढ़ में 70 हज़ार 157 मानक बोरा, कोरबा में 42 हज़ार 960 मानक बोरा तथा कटघोरा में 65 हज़ार 932 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ।
- इसके पश्चात् सरगुजा वनवृत्त के अंतर्गत 102 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि के 2 लाख 55 हज़ार 675 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण किया गया है। इनमें वनमंडलवार जशपुर में 23 हज़ार 297 मानक बोरा, मनेंद्रगढ़ में 32 हज़ार मानक बोरा, कोरिया में 20 हज़ार 996 मानक बोरा, सरगुजा में 30 हज़ार 645 मानक बोरा तथा सूरजपुर में 58 हज़ार 207 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण किया गया है।

नोट :

- इसी तरह कांकेर वनवृत्त के अंतर्गत 98 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि के 2 लाख 49 हज़ार 679 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है। इनमें वनमंडलवार पूर्व भानुप्रतापपुर में 91 हज़ार 320 मानक बोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 70 हज़ार 120 मानक बोरा, दक्षिण कोंडागाँव में 12 हज़ार 446 मानक बोरा तथा केशकाल में 21 हज़ार 107 मानक बोरा, नारायणपुर में 15 हज़ार 322 मानक बोरा, कांकेर में 34 हज़ार 364 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण किया गया है।
- वनवृत्त रायपुर के अंतर्गत 75 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि के एक लाख 88 हज़ार 527 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है। इनमें वनमंडलवार धमतरी में 22 हज़ार 890 मानक बोरा, गरियाबंद में 69 हज़ार 890 मानक बोरा, महासमुंद में 74 हज़ार 871 मानक बोरा तथा बलौदाबाज़ार में 20 हज़ार 877 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण किया गया है।
- वनवृत्त जगदलपुर के अंतर्गत 70 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के एक लाख 76 हज़ार 505 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण किया गया है। इनमें वनमंडलवार बीजापुर में 75 हज़ार 395 मानक बोरा, सुकमा में 75 हज़ार 913 मानक बोरा, दंतेवाड़ा में 10 हज़ार 395 मानक बोरा, जगदलपुर में 14 हज़ार 802 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है।
- इसके पश्चात् वनवृत्त दुर्ग के अंतर्गत 63 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि के एक लाख 58 हज़ार 653 मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है। इनमें वनमंडलवार राजनांदगांव में 65 हज़ार 559 मानक बोरा, खैरागढ़ में 34 हज़ार 698 मानक बोरा, बालोद में 20 हज़ार 383 मानक बोरा तथा कवर्धा में 38 हज़ार मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है।

दृष्टि The Vision

नोट :